



Neutral Citation No. - 2026:AHC:31109

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 4338/2026

मुन्ना

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: कमला प्रसाद, नरेंद्र कुमार यादव,

शिव पूजन

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी गई और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता ने संबंधित प्रतिवादी को वाद संख्या 1254/2024 (कंप्यूटर वाद संख्या T202414360501254) का शीघ्र निर्णय करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ यह याचिका दायर की है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें यह अनिवार्य है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर इसका निपटारा करना होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में कहा गया है,

"(7). तहसीलदार विवादित न होने पर भी, उत्परीवर्तन के मामले का निर्णय 45 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेगा।" मामले के पंजीकरण की तिथि और विवादित मामले के उत्परीवर्तन की कार्यवाही 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. उक्त प्रावधान के आलोक में और पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में, अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त आवेदन पर विचार करें और कानून के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, इसके गुण-दोष के आधार पर इसका निपटारा करें, लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

11 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"